

SOM DISTILLERIES AND BREWERIES LIMITED

Registered Office: I-A, Zee Plaza, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, Kamal Cinema Road, New Delhi - 110029
Phone: +91-11-26169909, 26169712 Fax: +91-11-26195897

Corporate Office: SOM House, 23, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh – 462011
Phone: +91-755-4278827, 4271271 Fax: +91-755-2557470

Email : compliance@somindia.com **Website:** www.somindia.com

CIN : L74899DL1993PLC052787

(BSE : 507514, NSE : SDBL)



SDBL/BSE/NSE/2025-26

13.08.2025

To

The Manager, Listing Department, NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED 'Exchange Plaza' C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051. cmllist@nse.co.in <u>Security ID: SDBL</u>	Dy. General Manager, Department of Corporate Services, BSE LIMITED, First Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001. corp.compliance@bseindia.com <u>Security ID: 507514</u>
--	--

Sub: Newspapers Advertisement - Extract of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter ended 30th June, 2025

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith an advertisement published in newspapers - Extract of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter ended 30th June, 2025 as specified in Regulation 33 of SEBI (LODR), Regulations, 2015.

The above-mentioned advertisement is published in Mint New Delhi, Mint Mumbai and Business Remedies New Delhi on August 13, 2025

The same has also been uploaded on the Company's website www.somindia.com

You are requested to kindly take the above information on record.

For Som Distilleries and Breweries Limited

Om Prakash Singh
Company Secretary and Compliance Officer

पीएमएफबीवाई के तहत 78.41 करोड़ आवेदनों का बीमा हुआ, 1.83 लाख करोड़ रुपए के ढावों का हुआ भुगतान



बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली (आईएनएस)।

लेटेस्ट सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत अब तक 78.41 करोड़ आवेदनों का बीमा हुआ है और 1.83 लाख करोड़ रुपए के ढावों का भुगतान हुआ है।

किसानों का नामांकन 2022-23 के 3.17 करोड़ से 32 प्रतिशत बढ़कर 2024-25 में 4.19 करोड़ हो गया है, जो योजना की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है। 18 फरवरी,

2016 को शुरू की गई पीएमएफबीवाई का उद्देश्य किसानों को एक सरल, किफायती और व्यापक फसल बीमा समाधान प्रदान करना है। यह योजना किसानों को सूखा, बाद, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीटों के हमले और पौधों की बीमारियों जैसे अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिमों से होने वाले फसल नुकसान से बचाती है। पीएमएफबीवाई बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक पूरे फसल चक्र को कवर करती है, जिसमें भंडारण के दौरान होने वाली क्षति भी शामिल है।

आधार से पहचान साबित करने की प्रक्रिया ने नया मुकाम किया हासिल, महज 6 महीनों में दोगुना हुए लेनदेन

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली (आईएनएस)।

केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन ने एक नया मानक स्थापित करते हुए मात्र 6 महीनों में दोगुना, 100 करोड़ से 200 करोड़ लेनदेन दर्ज किए हैं।

आधार फेस ऑथेंटिकेशन से आधार धारक अपनी पहचान तुरंत, सुरक्षित और संपर्क रहित तरीके से, कभी भी, कहीं भी, बिना किसी दस्तावेज के सत्यापित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के अनुसार, 10 अगस्त, 2025 को यूआईडीएआई ने फेस ऑथेंटिकेशन के 200 करोड़



ट्रांजैक्शन का ऐतिहासिक जख्न मनाया, जो भारत के निर्बाध, सुरक्षित और कागज रहित प्रमाणिकरण की ओर तेजी से बढ़ते कदम को दर्शाता है। आधार से पहचान साबित करने की प्रक्रिया अपनाने की गति तेजी से बढ़ रही है। जहां 2024 की छमाही तक 50 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए थे वहीं, लगभग पांच महीनों में जनवरी 2025 में यह संख्या दोगुनी होकर 100 करोड़ लेनदेन हो गई। मंत्रालय ने बताया कि छह

भारत में खुदरा महंगाई जुलाई में कम होकर आठ वर्षों के निचले स्तर 1.55 प्रतिशत पर रही

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली(आईएनएस)।

भारत में खुदरा महंगाई जुलाई में कम होकर 1.55 प्रतिशत हो गई है। यह महंगाई का 8 वर्षों (जून 2017) का सबसे निचला स्तर है। महंगाई में कमी आने की वजह खाद्य उत्पादों की कीमतों कम होना है। यह जानकारी सरकार की ओर से मंगलवार को दी गई। इससे पहले जून में खुदरा महंगाई दर 2.1 प्रतिशत थी, जो कि जनवरी 2019 के बाद से न्यूनतम स्तर था। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में खाद्य महंगाई दर घटकर -1.76 प्रतिशत रही। यह जनवरी 2019 के बाद खाद्य महंगाई दर का सबसे निचला स्तर है। जून के मुकाबले, इसमें 0.75 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

जुलाई 2025 के दौरान मुख्य महंगाई दर और खाद्य महंगाई दर में बड़ी गिरावट मुख्य रूप से अनुकूल आधार प्रभाव और दालों, सब्जियों, अनाज, अंडे और चीनी की महंगाई दर में कमी के कारण है। परिवहन, संचार और शिक्षा की लागत में कमी के कारण भी महंगाई दर कम हुई है। इसके अलावा, जुलाई के दौरान



हाउसिंग महंगाई में भी मामूली गिरावट आई है। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की खुदरा महंगाई दर 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसकी वजह मानसून की स्थिर प्रगति और खरीफ की अच्छी बुवाई से खाद्य कीमतों पर नियंत्रण रखने की उम्मीद है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में कहा, '2025-26 के लिए महंगाई का पूर्वानुमान जून में की गई अपेक्षा से अधिक नरम हो गया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की स्थिर प्रगति, अच्छी खरीफ बुवाई, पर्याप्त जलाशय

स्तर और खाद्यान्नों के पर्याप्त बफर स्टॉक के साथ बड़े अनुकूल आधार प्रभावों ने इस नरमी में योगदान दिया है।'

हालांकि, प्रतिकूल आधार प्रभावों और नीतिगत कदमों से उत्पन्न मांग संबंधी कारकों के प्रभाव में आने के कारण, खुदरा महंगाई 2025-26 की चौथी तिमाही और उसके बाद 4 प्रतिशत से ऊपर रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इनपुट कीमतों पर किसी भी बड़े नकारात्मक प्रभाव को छोड़कर, वर्ष के दौरान मुख्य महंगाई दर 4 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर रहने की संभावना है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अब तक 3.95 घटकर 6.64 लाख करोड़ रुपये रहा

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 3.95 प्रतिशत घटकर 6.64 लाख करोड़ रुपये रहा। कर संग्रह में कमी की मुख्य वजह 'रिफंड' का अधिक होना है। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। प्रत्यक्ष कर में कंपनियों, व्यक्ति , पेशेवरों और अन्य संस्थाओं की आय पर कर शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड



(सीबीडीटी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष एक अप्रैल से 11 अगस्त के बीच में अब तक जारी 'रिफंड' 10 प्रतिशत बढ़कर 1.35 लाख

करोड़ रुपये हो गया। शुद्ध कंपनी कर संग्रह तीन प्रतिशत बढ़कर करीब 2.29 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि गैर-कंपनी कर (जिसमें व्यक्ति , हिंदू अधिभाजित परिवार व कंपनी शामिल हैं) संग्रह 7.45 प्रतिशत घटकर 4.12 लाख करोड़ रुपये रहा। आंकड़ों के अनुसार, एक अप्रैल से 11 अगस्त के बीच प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) संग्रह 22,362 करोड़ रुपये रहा।

भारत की क्रेडिट डिमांड मजबूत, कुल एयूएम 121 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा : रिपोर्ट

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली (आईएनएस)। तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण, बढ़ती उपभोक्ता आकांक्षाओं और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर भारत की क्रेडिट डिमांड मजबूत बनी हुई है। यह जानकारी मंगलवार को आई रिपोर्ट में दी गई।

ग्लोबल डेटा और टेक्नोलॉजी कंपनी एक्सपेरियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मार्च 2025 तक इंडस्ट्री एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 121 लाख करोड़ रुपए थीं, जो सालाना आधार पर 21 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तिमाही के दौरान नए ऋण वितरण 16 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए, जो सालाना आधार पर 10 प्रतिशत और

तिमाही आधार पर 8 प्रतिशत की वृद्धि है। यह मुख्य रूप से गैल्ट लोन, बिजनेस लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (एलएपी) में निरंतर वृद्धि के कारण हुआ।

एक्सपेरियन के भारत में कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष जैन ने कहा, 'डिजिटलीकरण, बदलती उपभोक्ता आकांक्षाओं और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की पूछछूमि में भारत का क्रेडिट इकोसिस्टम लगातार विकसित हो रहा है।' उन्होंने आगे कहा कि हमारा लेटेस्ट क्रेडिट इनसाइट विशेष रूप से सुरक्षित ऋण और छोटे-टिकट वाले व्यक्तिगत ऋणों में इस मांग की संरचनात्मक गहराई को रेखांकित करता है, जो बढ़ते उपभोक्ता विश्वास और जिम्मेदारी उथारी दोनों की ओर इशारा करता है।

प्रमुख बंदरगाहों ने बीते 5 वर्षों में 13,355 करोड़ रुपए के 25 पीपीपी प्रोजेक्ट्स प्रदान किए : सर्वानंद सोनोवाल

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली(आईएनएस)।

पिछले पांच वर्षों में देश के प्रमुख बंदरगाहों ने 13,355 करोड़ रुपए के कुल 25 पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) प्रोजेक्ट्स प्रदान किए हैं। सरकार ने प्रमुख बंदरगाहों के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में पहचाना है। केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। गैर-प्रमुख बंदरगाहों का नियंत्रण राज्य प्राधिकरणों के पास है, जिनमें समुद्री बोर्ड भी शामिल है।

केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि प्रमुख बंदरगाहों में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, केंद्र सरकार ने प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 के स्थान पर प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को लागू किया है। साथ ही,



मॉडल कन्वेंशन एग्जिमेंट को संशोधित किया गया है और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए टैरिफ निर्धारण दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा, 'पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को 2024-25 में प्रमुख बंदरगाहों पर खराब कार्य स्थितियों और सुरक्षा उल्लंघनों की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।' एक अलग उत्तर में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने

आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, नए बर्थ और टर्मिनलों के निर्माण, पूंजीगत ड्रेजिंग और सड़क एवं रेल संपर्क को बढ़ाकर देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सोनोवाल ने कहा, 'तमिलनाडु राज्य में स्थित वी.ओ. चिदंबरम बंदरगाह प्राधिकरण, चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण और कामराजर बंदरगाह लिमिटेड ने पिछले 10 वर्षों में अपनी क्षमता में क्रमशः 177.12 प्रतिशत, 58.06 प्रतिशत और 162.16 प्रतिशत की वृद्धि की है।' इस बीच, राष्ट्रीय जलमार्गों पर पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) को 8 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटेमार्न के निर्माण का ऑर्डर दिया है। वाराणसी में एक हाइड्रोजन-ईंधन वाला सेल पोत भी तैनात किया गया है।

CONSOLIDATED RESULTS SHOWING GROWTH OF QFY 26 VS QFY 25

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025					
Sr. No.	Particulars	CONSOLIDATED			
		Quarter Ended		Year Ended	
		30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	31-Mar-25
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1.	Revenue from operations (Incl State Excise Duties)	88,454.63	68,275.33	1,01,270.93	2,83,072.98
2.	Profit/(Loss) before exceptional items and tax	5,838.31	3,246.69	5,603.75	14,367.89
3.	Profit/(Loss) before tax	5,838.31	3,246.69	5,603.75	14,367.89
4.	Profit/(Loss) for the Period	4,206.15	2,373.43	4,054.97	10,449.63
5.	Total Comprehensive Income for the Period				
	a) Owners of the Company	4,120.41	2,232.35	3,762.47	9,553.87
	b) Non-Controlling Interest	85.74	100.22	292.50	854.90
6.	Earnings Per Equity Share (Face Value of Rs. 1 each) (Under note no. 4)				
	Basic (in Rs.)	2.02	1.15	2.08	5.28
	Diluted (in Rs.)	2.03	1.15	2.07	5.28

Summarized Unaudited Standalone Financial Results of the Company is as under:					(Rs. in Lacs)
Sr. No.	Particulars	STANDALONE			
		Quarter Ended		Year Ended	
		30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	31-Mar-25
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1.	Revenue from operations (Incl State Excise Duties)	41,763.81	20,881.60	38,404.39	97,101.17
2.	Profit/(Loss) before tax	5,269.20	2,108.75	3,407.68	7,957.70
3.	Profit/(Loss) for the Period	3,782.82	1,598.14	2,402.26	5,772.47

- Notes:
- Unaudited financial results for the quarter ended 30th June 2025 reviewed by audit committee were taken on the record at the board meeting held on 11th August 2025.
 - The company is engaged in the business of manufacturing of alcoholic beverages. There are no reportable segments other than alcoholic beverages, which singly or in the aggregate qualify for separate disclosure as per provision of the relevant Ind AS 108 'Operating Segments'.
 - During the period resolution was passed at extra-ordinary general meeting of the members of the company on 30th April, 2024 for sub-division of equity share capital of the company from a face value of Rs. 5/- each to face value of Rs. 2/- each ('Sub-Division').
 - As per IndAS-33, earning Per Share for all periods presented in above statement have been adjusted based on total number of shares after sub-division of equity share from Rs.5 per share to Rs. 2 per share.
 - The above is an extract of the detailed format of the Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the said Financial Results is available on the Stock Exchanges websites on www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website www.somindia.com.
 - Previous Period figures have been regrouped and/or reclassified, wherever necessary.
 - Shareholders are requested to intimate change of address, if any.

Registered Office: I-1-A, Zee Plaza, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, Kamal Cinema Road, New Delhi - 110029
Corporate Office: SOM House, 23, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh - 462011
Phone: +91-755-4278827, 4271271 Fax: +91-755-2557470 Website: www.somindia.com Email: compliance@somindia.com